भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4684
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

स्नातकों की संख्या

†**4684. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंजीनियर, चिकित्सक, वकील और अन्य विषयों सहित विगत पांच वर्षों के दौरान स्नातक की डिग्री पाने वाले व्यक्तियों की वर्ष-वार और विषय-वार संख्या कितनी है;
(ख) इन स्नातकों में से वर्तमान में कितने लोग बेरोजगार हैं और इनमें से कितने स्नातक अन्य देशों में कार्यरत हैं; और
(ग) उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त अधिक से अधिक व्यक्तियों को देश में लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2016-17 से 2018-19 के अनुसार इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य विषयों सहित स्नातक करने वालों की संख्या निम्नानुसार हैः-

वर्ष	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	चिकित्सा विज्ञान	कानून	अन्य
2018-19	831504	226234	81153	5335824
2017-18	873406	203814	72486	5269933
2016-17	894437	186832	67973	5307144

(ख): उन स्नातकों, जो वर्तमान में बेरोजगार हैं और जो अब अन्य देशों में नियोजित हैं, का विशिष्ठ डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): देश में स्नातकों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के साथ ज्ञान, कौशल, अभिरूचि और सेवाकालीन प्रशिक्षण के विकास पर जोर देते हुए प्रशिक्षुता/अध्येतावृत्ति सहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कौशल अर्हता

फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तीन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें सामुदायिक कॉलेज (वर्ष 2013-14 से), बी.वॉक डिग्री कार्यक्रम (2014-15 से) और दीन दयाल विश्वविद्यालय (डीडीयू) कौशल केन्द्र (2015-16 से) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं के लिए एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के रूप में एक फ्लैगशिप योजना कार्यान्वित कर रहा है।

साथ ही, भारत में इंजीनियरिंग स्नातकों की नियोजनीयता को बेहतर बनाने की दृष्टि से लघु अवधि और मध्यावधि दृष्टिकोण योजना तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की कि:

(क) एआई, डाटा साइंस, आईओटी, साइबर सिक्युरिटी, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआर/वीआर, ब्लॉक चेन और 3डी प्रिंटिंग जैसी नौ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पाठ्यक्रम और इन्हें अवर स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में शुरू करना होगा।
(ख) पारंपरिक विषयों में सीटें कम करके और मौजूदा सीटों को इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करके बहु-विषयक पाठ्यक्रम पर अधिक फोकस।
(ग) उपयुक्त 9 (नौ) प्रौद्योगिकियों में एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ के साथ मिलकर एक मॉडल पाठ्यचर्या तैयार की गई है।

देश में स्नातक छात्रों, विशेषकर इंजीनियरिंग छात्रों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा किए जा रहे गुणवत्ता उपाय इस प्रकार हैं:

(i) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अवर स्नातक (यूजी) स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम तथा पीजीडीएम/एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करना।
(ii) इंजीनियरिंग में अवर स्नातक स्तर पर पहले वर्ष के शुरू होते समय ही छात्रों के लिए 3 सप्ताह का प्रवेश कार्यक्रम शुरू करना।
(iii) प्रवेश कार्यकलापों की निगरानी के लिए एआईसीटीई में प्रवेश प्रकोष्ठ और 'छात्र प्रवेश कार्यक्रम' पर संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण का समन्वयन करने के लिए राष्ट्र स्तरीय समन्वय समिति का गठन।
(iv) परीक्षा सुधार तथा व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करना। पदधारक तथा सेवारत शिक्षकों के लिए 8 मॉडयूल प्रस्तावित हैं।
(v) अनिवार्य इंटर्नशिप, मॉडल पाठ्यचर्या का संशोधन और उद्योग रेडिनेस प्रत्यायन।
(vi) छात्रों की बुनियादी क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं के प्री-फाइनल और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए व्हीबाक्स नियोजनीयता कौशल परीक्षा (वेस्ट) का आयोजन किया जा रहा है।

*****